ISSN: 2277-9876

Indian Journal of New Dimensions

Volume : II Number: 1 Jan.-Jun. 2012

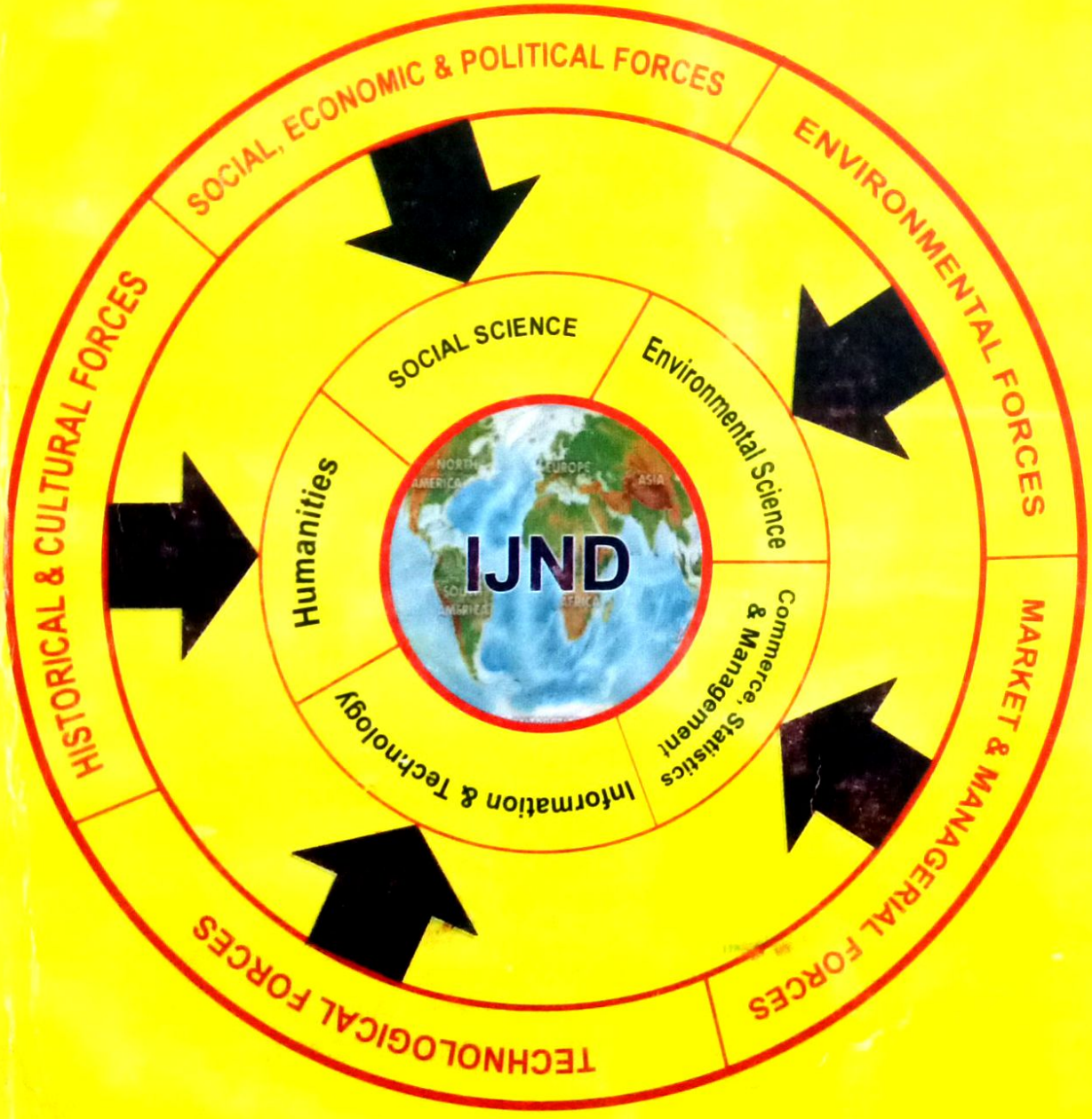

Dr. Lal Mrigendra Singh Baghel
Chief Editor
Dr. Vijay Pratap Mall
Editor

Jawahar Lal Nehru Memorial Post-Graduate College Barabanki.
2012

INDIAN JOURNAL OF NEW DIMENSIONS

CONTENTS

1. SECULARISM AND COMMUNAL HARMONY IN INDIA: LOOMING QUESTIONS 1-4
Prof. PK CHAUBEY
2. FOOD AND NUTRITION SECURITY: SOME ISSUES 5-18
Prof. Neelkanth Gajanan Pendse
3. SOCIO-POLITICAL & ECONOMIC REASONS BEHIND THE NAXALISM: AN ANALYSIS OF FACTS & FUTURE ASPECTS 19-25
Dr. Lal Mrigendra Singh Baghel
4. INFORMAL SECTOR IN INDIA with Special Reference to Uttar Pradesh: A SECTOR OF RELEVANCE YET IN DILEMMA 26-31
Anamika Choudhary
5. KNOWLEDGE MANAGEMENT: A TOOL TO IMPROVE COMPETITIVENESS FOR INDIAN BANKS: A STUDY OF PUNJAB NATIONAL BANK, JABALPUR CIRCLE 32-40
Prof. Chandrashekhar Aronkar
6. EDUCATION INCLUSION OF GIRLS IN HIGHER EDUCATION IN INDIA 41-50
Dr. Veena Thawre
7. GROWTH OF SMALL SCALE INDUSTRIES IN INDIA: PAST AND PRESENT 51-60
Mrs Renu Markande
8. THE SIGNIFICANCE OF COOPERATIVES IN GLOBAL ECONOMIC AND SOCIAL CHANGE 61-62
Yatish Jain & Mathuresh N. Jayaswal
9. 21सदी भूमण्डलीकरण और गांधी 63-66
डा0 विजय प्रताप मल्ल
10. वैश्वीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में गठबन्धन सरकारों के समक्ष उभरती चुनौतियाँ 67-70
डॉ० जयकुमार मिश्र
11. ANGLO-CATHOLIC SENTIMENTS IN THE POEMS OF THOMAS STEARNS ELIOT 71-82
Dr. Mrs.Judith Singh
12. REGIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT 83-95
Dr. (Ms.) Anita Nayak
13. EMPLOYMENT OPPORTUNITIES IN TOURISM SECTOR OF INDIA 96-102
Dr. Giridhari Prasad Das
14. INDIAN COMPANIES IN KNOWLEDGE ECONOMY 103-107
Mr. Vinamra Nayak
15. NATIONAL RURAL HEALTH MISSION: ISSUES AND CHALLENGES IN U.P. 108-112
Dr. Ashok Kaithal
16. POWER SECTOR REFORMS: THE IMPACT OF NEW LEGISLATION 113-119
Dr. Mrs. Elena Philip
17. AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN INDIA IN PATENT REGIME 120-127
Dr. Mathuresh Narayan Jayaswal
18. RATIONAL ANALYSIS VERSUS INTUITION IN DECISION MAKING IN ORGANISATIONS 128-131
Prof. Sandeep Singh
19. INDIA: "THE EMERGING GIANT" *By Arvind Panagariya* 132-133
Oxford University Press, Hardback, Feb 2008, pages-544.
BOOK REVIEWED *BY DR. Lal Mrigendra Singh Baghel*

वैश्वीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में गठबन्धन सरकारों के समक्ष उभरती चुनौतियाँ

डॉ० जयकुमार मिश्र
अध्यक्ष, राजनीतिविज्ञान विभाग,
राजा हरपाल सिंह पी०जी० कालेज सिंगरामऊ, जौनपुर

1990 ई० के बाद का काल भारतीय राजनीति एवं अर्थव्यवस्था दोनों में ही गम्भीर और गहरे परिवर्तन का साक्षी रहा है। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना ने जहाँ जनता को जातीय, धार्मिक एवं क्षेत्रीय हितों के प्रति अधिक चैतन्य कर दिया, वहीं विश्व बाजार से जुड़ने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था भी अधिक गतिशील एवं एकीकृत होने लगी। राजनीतिक परिदृश्य पर जहाँ राष्ट्रीय दलों का ह्रास और क्षेत्रीय दलों के आविर्भाव का युग प्रारम्भ हुआ, वहीं अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, बाजारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का अध्याय जुड़ गया। 1990 के बाद भारत में केन्द्रीय स्तर पर संविद या गठबंधन सरकारों के अभिनव प्रयोग प्रारम्भ हुए, बढ़ती हुई क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीतिक चेतना के कारण किसी भी दल की केन्द्र में अकेले दम पर सरकार बनाने की क्षमता जाती रही और गठबंधन के रूप में सरकारों की स्थापना एक नयी विवशता के रूप में भारतीय राजनीति का यथार्थ बन गयी, जो निरन्तर प्रवहमान है। इन सबके परिणामस्वरूप यह मान्यता अब परिवर्तित हो रही है कि संसदीय लोकतंत्र में दो दल होने चाहिए, क्योंकि 1990 के बाद का भारतीय संसदीय लोकतंत्र, दो प्रमुख दलों (भाजपा और कांग्रेस) के नेतृत्व में बहुदलीय संसदीय प्रणाली में बदलता जा रहा है। पिछले 15–20 वर्षों में इस व्यवस्था के अधीन काम करते हुए क्षेत्रीय दलों तथा गठबंधन सरकारों ने बहुत कुछ सीखा है और क्षेत्रीय दलों में गठबन्धन सरकारों की तथा गठबन्धन सरकारों ने क्षेत्रीय दलों की सोच एवं कार्यपद्धति को परस्पर बहुत प्रभावित किया है। इसे हम कुछ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों एवं वैश्वीकरण के सन्दर्भ में समझने का प्रयास करेंगे।

अन्तर्राश्ट्रीय मुद्दे, घटक दल और गठबन्धन सरकार –

आज गठबन्धन सरकारों में शामिल क्षेत्रीय दल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपने विचार व्यक्त करने लगे हैं, जो अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश के प्रति उनकी बढ़ती जागरूकता का प्रमाण है। यह हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के और भी अधिक लोकतान्त्रिक बनने का प्रतीक है, लेकिन अनेक बार यह देखा गया है कि गठबंधन सरकार में शामिल क्षेत्रीय दल किसी विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय घटना को अपनी 'परम्परागत प्रतिबद्धताओं के चश्में' से देखते हैं और इसके परिणामस्वरूप गठबन्धन सरकार की नीतियों से उस क्षेत्रीय दल की विचारधारा मेल नहीं खाती। परिणामतः सरकार में तनाव एवं दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं –

तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीति में श्रीलंका में बसे तमिलों के प्रति वैचारिक–व्यावहारिक दृष्टिकोण किसी भी दल के अस्तित्व एवं भविष्य का निर्धारक बन जाता है। वहाँ सत्ता प्राप्त करने के लिए सभी राजनीतिक दल श्रीलंका के तमिल पृथकतावादी आन्दोलन का समर्थन करते हैं। तमिलनाडु के एक क्षेत्रीय दल पट्टालि मक्कल काँची ने अपनी क्षेत्रीय राजनीति को जारी रखते हुए केन्द्रीय मनमोहन सिंह सरकार से यह माँग की, कि श्रीलंका में पृथक तमिल राष्ट्र को मान्यता दे दी जाय। कुछ वर्ष पूर्व तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से श्रीलंका में सशस्त्र हस्तक्षेप करने को कहा गया। इसी प्रकार 23 जनवरी, 2009 ई० को तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार से यह माँग की कि वह श्रीलंका सरकार से तमिलों के विरुद्ध निर्णायक कार्यवाही बन्द करने को कहे। ध्यान रहे द्रमुक केन्द्र में गठबन्धन सरकार, यूपीए का एक घटक दल भी है। द्रमुक की इस प्रकार की माँगें गठबन्धन सरकार को 'परेशान' करती रही है (देखें, नवम्बर, 2008 में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपक्षे की भारत यात्रा में भारत सरकार के वार्ता के मुद्दे और दिसम्बर, 2008 ई० में श्रीलंका सेना के प्रमुख शरत फोसेंका के वक्तव्य' के बाद भारत सरकार की सक्रियता – इन सबके पीछे द्रमुक द्वारा गठबन्धन सरकार पर डाला गया दबाव ही था।)

भारत में कुछ ऐसे भी राजनीतिक दल हैं, जो अरब–इजराइल संघर्ष के प्रश्न पर अरब जगत का खुला समर्थन और इजराइल की खुली आलोचना करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी में जब भारत ने ईरान के विरुद्ध मतदान किया था या जब भारत ने अमेरिका के साथ 2008 ई० में परमाणु समझौता किया तो अनेक क्षेत्रीय दलों (जिसमें से कुछ क्षेत्रीय दल तत्कालीन यूपीए की गठबन्धन सरकार में शामिल थे) ने भारत सरकार को ऐसा करने से रोकने का प्रयास किया। इसी प्रकार जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि यदि संसद पर हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरू को फाँसी दी गयी, तो पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध खराब हो जाएंगे और भारतीय मुसलमानों को भी गलत सन्देश जाएगा (2011 ई०)। इसी प्रकार 'द सेटेनिक वर्सेज' के लेखक सलमान रूसदी को भारत सरकार ने वीजा देने का मन बनाया, तो अनेक क्षेत्रीय दलों (उसमें से कुछ यूपीए में शामिल हैं) ने यूपीए सरकार की आलोचना की

(09 जनवरी, 2012)। ऐसा आचरण वे अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की किसी विशिष्ट समझ या भारत के हितों के आधार पर नहीं कर रहे थे, वरन् भारतीय मुसलमानों की अरब जगत् या इस्लामिक राष्ट्रों के साथ धार्मिक–मानसिक तादात्म्य/सामंजस्य के कारण करते रहे हैं तथा उनके वोट बैंक या इस्लामवाद के अनुकूल अपनी अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिकताएं तय करते हैं।[2] जब क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्रीय हितों पर आधारित नीतियों को राष्ट्रीय नीतियों पर वरीयता देते हैं तो इससे गठबन्धन सरकार के ऊपर अस्तित्व का नया संकट पैदा होने लगता है। अनेक बार तो क्षेत्रीय दल गठबन्धन सरकार को गिराने का भय दिखाकर अपनी निजी विचारधारा को थोपने का प्रयास करते दिखाई देते हैं, जो भारतीय राजनीति में उभरती उनकी नई विखण्डनकारी भूमिका का संकेत है।

वैश्वीकरण, घटक दल और गठबंधन सरकार –

गठबन्धन सरकारों द्वारा शासित होने के बावजूद भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया को भारत ने आगे बढ़ाने का कार्य कुशलतापूर्वक किया है। गठबन्धन सरकारों में शामिल घटक दलों की प्रायः यह मंशा रही है कि वैश्वीकरण हमारी अर्थव्यवस्था के लिए तभी अच्छा है, जब यह सामाजिक सुरक्षा की परम्परागत अवधारणा के साथ एकीकृत हो एवं इससे क्षति उठाने वालों को पर्याप्त मदद कर दी जाय। घटक दलों का यह कहना उचित तो है, लेकिन इलाज की पद्धति पर अधिक बल देने से बचना चाहिए, क्योंकि रोग का निदान महत्वपूर्ण है, वैश्विक एकीकरण से पैदा होने वाले जोखिमों से बचने के बजाय संकट की स्थिति में नीतिसंगत प्रतिक्रिया देना केन्द्रीय गठबन्धन सरकार का दायित्व है, अतः परिस्थितियों का सही आंकलन करके वित्तीय अनुशासन एवं राजकोषीय प्रतिबद्धता दिखाने की आवश्यकता का दायित्व घटक दलों का भी है। वस्तु एवं सेवा कर (ळैण्ज्) और खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का विरोध यूपीए के घटक दलों ने जिस प्रकार किया[3] और इस मुद्दे पर गठबन्धन सरकार को जिस प्रकार की समस्या उठानी पड़ी है, इसने हमारी वैश्वीकरण के प्रति वचनबद्धता को संशय की दशा में ला खड़ा किया है। यदि गठबन्धन सरकार उपरोक्त दोनों मुद्दों पर घटक दलों से पहले ही बातचीत कर सहमति कायम करने के बाद इन नीतियों को क्रियान्वित करती तो शायद बेहतर संदेश जाता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने गठबन्धन सरकार की इस प्रकार की नीतिगत समस्याओं के बारे में कहा है कि गठबन्धन सरकार मे उद्योग मंत्रालय किसी दूसरे घटक दल के हाथ में है, वित्त मंत्रालय पर किसी अन्य दल का नियंत्रण है और प्रत्येक दल की अपनी निजी राजनीतिक विचारधारा है। फलतः गठबन्धन सरकार की निर्णय क्षमता एवं नीति–निर्माण क्षमता दोनों ही प्रभावित हो जाती है।

वैश्वीकरण के युग में यह भी देखने को मिला है कि वे भारतीय कम्पनियां जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में छायी दुर्बलताओं पर प्रायः खामोश रहती थी, वे भी अब गठबंधन सरकारों के घटक दलों में आर्थिक सुधारों के प्रति बढ़ती उदासीनता एवं इस कारण वित्तीय सुधारों में हो रहे विलम्ब को लेकर अपनी चिन्ताएं और आलोचनाएं खुलकर व्यक्त करने लगी हैं। यूपीए में कांग्रेस यह बात अच्छी प्रकार से समझती है कि देश में आर्थिक सुधारों के प्रति उत्साह एवं उज्ज्वल भविष्य आवश्यक है, लेकिन वह घटक दलों की क्षेत्रीय रुचियों एवं उनकी आर्थिक सुधारों के प्रति राष्ट्रीय सोच के अभाव को भी अच्छी प्रकार से समझती है तभी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इन कमियों का ठीकरा यूपीए के घटक दलों पर फोड़ते हुए कहा कि, गठबन्धन राजनीति के युग में प्रायः सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि, वह प्रमुख नीतिगत मुद्दो पर सहमति कायम करे और अनेक बार सहमति तक पहुँचने में समय लग जाता है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का संकेत उन संरचनात्मक और संस्थात्मक सुधारों की ओर है, जो यूपीए–2 में घटक दलों की क्षुद्र मानसिकता के कारण विलम्बित हैं। सिंगूर एवं नंदीग्राम (प० बंगाल) में तृणमूल कांग्रेस तथा उत्तर–प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे तथा रायबरेली में रेलवे की फैक्ट्री लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने के समय क्षेत्रीय दलों का जो विरोध प्रदर्शन किया गया, वह इस बात को दर्शाता है कि गठबंधन सरकार के साथ रहकर भी क्षेत्रीय दल अपने को राष्ट्रीय हितों के साथ एकीकृत करने में संयम एवं दूरदर्शिता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं।

विनिवेश के प्रश्न पर भी गठबन्धन सरकार के घटक दलों के बीच आम सहमति स्थापित न होने के कारण यह प्रक्रिया भी गति नहीं पकड़ पा रही है। वर्ष 2011–12 में यूपीए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य रुपया 40 हजार करोड़ निर्धारित किया था, लेकिन सरकार अब तक (13 जनवरी, 2012) तक केवल रुपया 1145 करोड़ ही जुटा सकी है। 4 जनवरी, 2012 को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कम्पनियों में विनिवेश के प्रस्ताव पर बुलाई गई बैठक में यूपीए के घटक दलों के बीच कोई सहमति नहीं हो सकी, क्योंकि सबके अपने–अपने सुर थे।[4] यदि विनिवेश की यह प्रक्रिया पूरी हो जाती तो कम–से–कम इस वित्तीय वर्ष में यूपीए ने एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया होता। 1990 में प्रारम्भ वैश्वीकरण की प्रतिस्पर्द्धी प्रक्रिया में भी केन्द्रीय गठबन्धन सरकारों ने आर्थिक मोर्चों के विभिन्न स्तरों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। 1990 के बाद से भारत में जितनी भी गठबंधन सरकारें हुई हैं, उनकी यह संयुक्त सफलता मानी जानी चाहिए कि उन्होंने भारत को

हिन्दू विकास दर[5] (अर्थात् 3–4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर वाली अर्थव्यवस्था) से बाहर लाकर इसे विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं (7–10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाओं) की पंक्ति में ला खड़ा किया है, लेकिन यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि 1991 में भारत का चालू खाता घाटा जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत था, जबकि आज इसका स्तर 3.6 प्रतिशत है। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के अभाव का ही परिणाम है कि यूपीए ने 20 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है, जबकि उपलब्धि केवल 9 किलोमीटर प्रतिदिन ही है। गठबंधन सरकार में शामिल घटक दलों की पारस्परिक खींचतान के चलते ही विभिन्न आर्थिक सुधार एवं नीतिगत परिवर्तन रुके हुए हैं और राजनीतिक प्रबंधन अत्यन्त कमजोर हो गया है। वस्तुतः गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दल सरकार बनाने को लेकर तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय दलों की कोई अखिल भारतीय सोच न होने के कारण नेतृत्वकर्ता दल को प्रायः समस्याओं एवं उलझनों का सामना करना पड़ता है। एनडीए में भाजपा तथा यूपीए में कांग्रेस के सामने प्रायः इस प्रकार की चुनौतियाँ आती रही हैं। आर्थिक निर्णयों पर क्षुद्र राजनीति की छाया से अर्थव्यवस्था के प्रति अस्थायित्व की संभावना उद्योग–जगत को प्रायः संकट के संशय में डाल देती है, जिससे आर्थिक बिन्दु पर सरकार की क्षमता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की अर्थव्यवस्था की रेटिंग घटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

पिछले 20 वर्षों में गठबंधन सरकारों को अनेक बार राजनीतिक प्रश्नों पर गम्भीर नैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है। एनडीए सरकार ने लालू शासित बिहार राज्य में जब कानून–व्यवस्था की खराब स्थिति को आधार मानते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने का निर्णय लिया था, तो यह निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक था और नीतिश कुमार एवं अन्य सहयोगी नेताओं के दबाव में लिया गया निर्णय था, क्योंकि वाजपेयी जी जिस गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, वह इन घटक दलों के समर्थन पर ही टिकी थी। वह तो अच्छा हुआ कि तत्कालीन राष्ट्रपति ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने यह कहते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने से मना कर दिया कि कानून–व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, जिसे आधार मानकर किसी चुनी हुई राज्य सरकार को बरखास्त करना उचित नहीं है। निश्चित रूप से यह गठबंधन सरकार की विवशता को दर्शाता है। इसी प्रकार 2–जी स्पेक्ट्रम घोटाले में कैग द्वारा आरोपित होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार संचार मंत्री ए० राजा का बचाव किया और न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर सरकार ने यह कहा कि वे निर्दोष हैं, वह गठबंधन सरकार की मजबूरी को दर्शाता है। बाद में ए० राजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन इन घटनाओं ने गठबन्धन सरकार की विवशता को अक्षरशः स्पष्ट कर दिया है, जो शुभ संकेत नहीं है।

निश्कर्ष –

वस्तुतः क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति के स्थायी चरित्र बन चुके हैं। फलतः गठबन्धन की राजनीति अनिवार्य व्यवहार बन गयी है। गठबन्धन की सरकार को जब कोई दल बाहर से समर्थन देता है तो कटुता की सम्भावना तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है, क्योंकि ऐसे दल उत्तरदायित्व का निर्वहन किए बिना ही अपनी बढ़ी हुई हैसियत का प्रयोग कर रहे होते हैं। अनुभव बताता है कि चुनावों के समय आपस में तीव्र प्रतिद्वन्दिता के बाद साथ रहकर गठबन्धन सरकार का संचालन करना कठिन हो जाता है और अनेक बार ऐसे गठबन्धन में शामिल घटक दल सत्ता में रहते हुए भी विपक्षी की भूमिका जाने–अनजाने निभाने लगते हैं। इसी कारण वाजपेयी जी के नेतृत्व में बने राजग (एनडीए) के कार्यकाल (1999–2004 ई०) में उन्हें विपक्ष से उतनी समस्या पैदा नहीं हुई, जितनी कि राजग में शामिल घटक दलों से और यही हाल यूपीए का भी रहा है। भारत में विभिन्न दलों की गठबंधन सरकारें बनाने और सुचारु रूप से प्रशासन चलाने के मार्ग में जो बाधाएं हमारे सामने आयी हैं, उनकी जड़ें घटक दलों की सामाजिक और आर्थिक विचारधारा में छिपी हुई है, जो उन्हें अपनी संकुचित प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलने ही नहीं देतीं। क्षेत्रीय दलों के सामने यह मनोवैज्ञानिक एवं सैद्धान्तिक समस्या होती है कि, वे यदि क्षेत्रीय मुद्दों या हितों की अनदेखी करके राष्ट्रीय हितों के साथ जुड़ जाएं, तो उनके क्षेत्रीय अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि तब वे क्षेत्रीय हितों की पूर्ति नहीं कर पाएंगे और यदि वे क्षेत्रीय हितों के प्रति मजबूती से प्रतिबद्ध हो जाते हैं, तो उनकी राष्ट्रीय भूमिका निभाने और राष्ट्रीय दल के रूप में परिवर्तित होने की सम्भावना ही नष्ट होने लगती है और इससे अन्य क्षेत्रों की जनता को लगता है कि यह क्षेत्रीय दल अत्यन्त संकीर्ण सोच वाला है अतः क्षेत्रीय दल हमेशा एक डोलड्रम (क्या करें या क्या न करें) की मनोदशा में रहते हैं और वे गठबंधन सरकार में शामिल होकर भी कोई राष्ट्रीय भूमिका नहीं निभा पाते और न ही कोई राष्ट्रीय छवि ही बना पाते हैं। 1990 ई० के बाद भारत में जाति, भाषा, धर्म, प्रान्त आदि के आधार पर बने क्षेत्रीय दलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, इसे जनता की बढ़ती हुई राजनीतिक–लोकतान्त्रिक चेतना से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि, राजनीतिक रूप से भारतीय समाज निरन्तर असहिष्णुता की ओर बढ़ रहा है। समाज में गठबन्धन नहीं है, लेकिन राजनीति में गठबन्धन बन रहे हैं, जो सत्ता की प्राप्ति हेतु दर्शायी जाने वाली सहिष्णुता है। सहिष्णु समाज के

अभाव में सहिष्णु राजनीति दीर्घजीवी कैसे हो सकती है? इसी कारण भारत में राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का गठबंधन तो होता है लेकिन नीतियों एवं विचारों का गठबंधन नहीं हो पाता है। वस्तुतः गठबंधन सरकारों में शामिल घटक दल कभी–कभी यह समझ नही पाते कि गठबन्धन सरकार और सत्ता की साझेदारी का सम्पूर्ण विचार औचित्य[6] और निष्पक्षता[7] पर आधारित होता है। यदि गठबंधन में शामिल घटक दलों में सामान्य औचित्य एवं निष्पक्षता का अभाव है तो वे जनता की सेवा के आधार पर गठबन्धन सरकार को निरन्तर गतिमान रखने में असफल हो जाएंगी। गठबंधन सरकार में शामिल दलों को नीतिगत प्रश्नों पर पारस्परिक समझौते की कला का विकास करने की आवश्यकता है। यूरोप के राजनीतिक दलों ने इस कला का विकास कर लिया है, वहाँ गठबंधन सरकारें इसीलिए सफल होती हैं, कि वे न्याय एवं औचित्य के आधार पर सत्ता में सहभागी या साझीदार बनाना सीख चुके हैं, जबकि भारत के राजनीतिक दलों को यह सीखना बाकी है।[8] भारत में गठबन्धन राजनीति उत्शृंखलता का शिकार न होने पाए, कोई भी घटक दल सरकार को गिराने का भय दिखाकर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरा न करे या क्षेत्रीय हितों के आगे भारत के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हितों को दुष्प्रभावित करने की कोशिश न करे, इसके लिए एक 'गठबंधन धर्म' बनाने की आवश्यकता है। आशा है भारत के राजनीतिक दल इसके लिए तैयार हो जाएंगे।

सन्दर्भ–सूत्र

1. डॉ० जयकुमार मिश्र और डॉ० अखिलेश्वर शुक्ला – "भारत का संविधान : एक पुनर्दृष्टि", कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010, पृ०–309.
2. वही, पृ० 310.
3. खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का विरोध तृणमूल कांग्रेस तथा द्रमुक ने किया, जबकि दोनों यूपीए की गठबंधन सरकार के सक्रिय सहयोगी घटक दल हैं। इसी प्रकार सपा ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का विरोध किया था, जबकि वह भी यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही है। वस्तु एवं सेवा कर को भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने ही लाया था, लेकिन अब जबकि यूपीए इसे लागू करना चाहती है तो भाजपा के नेतृत्व में एनडीए इसके विरोध में उतर गयी है।
4. बिजनेस स्टैण्डर्ड, लखनऊ, 5 जनवरी, 2012[9]
5. यह अवधारणा अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने प्रस्तुत की थी, जिसके अनुसार 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि वाली भारतीय अर्थव्यवस्था को 'हिन्दू वृद्धि दर' कहा गया।
6. यहाँ औचित्य का तात्पर्य जनता की सेवा के औचित्य से है।
7. निष्पक्षता का तात्पर्य है कि गठबंधन सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को अपनी दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्षता से प्रस्तुत करना और स्वीकार करना। गठबंधन को अपने दल से ऊपर मानना चाहिए।
8. मधु लिमये, 'भारतीय राजनीति के अन्तर्विरोध', सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996, पृ०–76.